पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की बढ़ी उम्मीद

जुलाई-सितंबर तिमाही से बेहतर नतीजों की उम्मीद

ईंधन मूल्य वृद्धि और सरकारी राहत का दिखेगा असर

नई दिल्ली, 23 जून पश्चिम एशिया में शांति समझौते के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. इसका सीधा लाभ भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों को मिलने लगा है.

पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर होने वाला घाटा काफी कम हो गया है, जिससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद बढ़ी है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी का यह दौर जारी रहा तो आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है

ब्रोकरेज फर्म जेपी मोरगन चेस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी रिफाइनरियों और खुदरा ईंधन विक्रेताओं का संयुक्त मार्जिन अब पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले के स्तर से भी ऊपर पहुंच गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में की गई कटौती ने कंपनियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है. जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 115 डॉलर प्रति बैरल थी, तब तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 23 रुपये और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था. लेकिन हालिया आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल पर यह घाटा घटकर मात्र तीन रुपये प्रति लीटर रह गया है. इससे कंपनियों के परिचालन प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है.

> हालांकि, कंपनियों पर बढ़ता कर्ज और भविष्य में ईंधन करों को लेकर अनिश्चितता अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. एलपीजी पर अंडर-रिकवरी का दबाव भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. फिर भी कच्चे तेल की कीमतों में जारी नरमी से तेल क्षेत्र में राहत का माहौल है और आम उपभोक्ताओं को भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी की उम्मीद बंधी है.

वैश्विक दबाव में लुढ़के शेयर बाजार

मुंबई, 23 जून विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों और आईटी सेक्टर पर दबाव के कारण घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी गयी और प्रमुख सूचकांक एक प्रतिशत से अधिक टूट गये.

बीएसई का सेंसेक्स 893.39 अंक (1.16 प्रतिशत) लुढ़ककर 76,200.68 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 278.80 अंक यानी 1.16 प्रतिशत नीचे 23,824.10 अंक पर रहा. यह दोनों का 12 जून के बाद का निचला स्तर है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आने वाले समय में महंगाई को काबू करने के लिए कठोर उपायों की आशंका में आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट रही. भारतीय शेयर बाजारों पर भी उसी का असर देखा गया,

8 साल बाद ईरानी तेल की वापसी

अमेरिका की 60 दिन की छूट से वैश्विक बाजार में बढ़ेगी तेल आपूर्ति

नई दिल्ली, 23 जून करीब आठ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ईरानी कच्चे तेल की वैश्विक बाजार में वापसी का रास्ता खुल गया है. अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर 60 दिनों की अस्थायी छूट (वाइवर) जारी की है, जिसके तहत 21 अगस्त 2026 तक ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री, परिवहन और वित्तीय लेनदेन की अनुमति दी गई है.

इस फैसले से वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने की संभावना है. भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है, इस बदलाव से सबसे बड़े लाभार्थियों में हो सकता है

पश्चिम एशिया में शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने

ईरानी तेल पर लगे कई प्रतिबंधों में अस्थायी राहत दी है. इस कदम के तहत ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में खुलकर तेल बेचने की अनुमति मिलेगी. रिपोर्टों के अनुसार, यह छूट परमाणु कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण और जलमार्ग सुरक्षा से जुड़े समझौतों के बदले दी गई है. इसके बाद वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कीमतों पर दबाव बना है और ब्रेंट तथा डब्ल्यूटीआई दोनों में गिरावट देखी गई है.

> यदि ईरान की आपूर्ति लगातार बढ़ती है और वैश्विक बाजार में अतिरिक्त तेल आता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी आ सकती है. बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि ईरान प्रतिदिन 1.5 से 2 मिलियन बैरल तक अतिरिक्त तेल बाजार में ला सकता है. इससे आयातक देशों को राहत मिलेगी और भारत में तेल विपणन कंपनियों की लागत घट सकती है. नतीजतन, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम होगा तथा भविष्य में उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना बढ़ेगी. हालांकि अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि 60 दिन की यह छूट आगे बढ़ती है या नहीं और वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रहती हैं.

अडानी के मुंद्रा एयरपोर्ट से शुरू हुईं वाणिज्यिक उड़ानें

मुंद्रा, 23 जून अडानी समूह के मुंद्रा एयरपोर्ट से मंगलवार को मुंबई और गोवा को जोड़ने वाली पहली निर्धारित उड़ान सेवा शुरू हुई.

स्टार एयर ने यहां से उड़ानों की शुरुआत की है. हवाई अड्डा शुरू होने के बाद मुंद्रा पूर्ण रूपेण एकीकृत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स और व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित होगा. स्टार एयर मुंद्रा को हिंडन, सूरत, बेलगावी, बेंगलुरु, कोल्हापुर और नांदेड़ सहित अन्य शहरों से भी जोड़ेगी. इससे व्यापार, वाणिज्य, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन के लिए एक तेज संपर्क गलियारा विकसित होगा, परिवहन के समय में उल्लेखनीय कमी आयेगी और मुंद्रा बंदरगाह की आर्थिक गतिविधियों को नयी गति मिलेगी. मुंद्रा एयरपोर्ट का रनवे 1,900 मीटर लंबा है. यह हवाई संपर्क अंतिम पड़ाव तक महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है, जिससे बंदरगाह के माध्यम से होने वाले विशाल व्यापार प्रवाह का अधिक कुशल प्रबंधन संभव होगा और इसे राष्ट्रीय तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सकेगा. अडानी समूह पहले से नवी मुंबई, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु गुवाहाटी हवाई अड्डों का परिचालन कर रहा है.

रिलायंस एडीए ग्रुप के दो पूर्व सीईओ गिरफ्तार

7,623 करोड़ के बैंक घोटाले : बैंकों को भारी नुकसान का आरोप

नई दिल्ली, 23 जून केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ा कदम उठाते हुए रिलायंस एडीए समूह से जुड़ी कंपनियों के दो पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई रुपए 7,623 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है.

आरोप है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए ऋणों को नियमों के खिलाफ अन्य समूह कंपनियों में डायवर्ट किया गया, जिससे बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ एजेंसी के अनुसार, आरसीएफएल मामले में 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लगभग ?4,097 करोड़ और आरएचएफएल मामले में 10 बैंकों को ?3,526 करोड़ का

नुकसान हुआ है. जांच में यह भी सामने आया है कि ये ऋण कथित तौर पर मध्यस्थ और शेल कंपनियों के जरिए जारी किए गए, जो नियमों और आरबीआई दिशानिर्देशों के खिलाफ था

जांच एजेंसी का दावा है कि यह प्रक्रिया ऋण नीति, आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक के नियमों का उल्लंघन करती है. आरोप है कि इन ट्रांजैक्शंस के जरिए बैंकों को गुमराह किया गया और फंड का गलत इस्तेमाल किया गया

सीबीआई ने इस पूरे मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरएचएफएल, आरसीएफएल और रिलायंस टेलीकॉम से जुड़े मामलों में कुल सात एफआईआर दर्ज की हैं.

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट

नई दिल्ली, 23 जून आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे खरीदारों और निवेशकों के बीच चर्चा का माहौल बन गया है. सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम लगभग 1600 रुपये तक की कमी दर्ज की गई, जबकि चांदी 6000 रुपये से अधिक सस्ती हो गई. कीमतों में आई इस गिरावट का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती को माना जा रहा है. मजबूत होता है, तब सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की मांग कम हो जाती है. इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता का भी असर बाजार पर पड़ा है. यही वजह है कि निवेशकों ने कीमती धातुओं में बिकवाली बढ़ा दी, जिससे कीमतें नीचे आ गईं.

अब निष्क्रिय वॉलेट पर लगेगा 100 रुपए शुल्क

नई दिल्ली, 23 जून. डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने अपने वॉलेट उपयोगकर्ताओं के लिए नया नियम लागू किया है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जो फोनपे वॉलेट पिछले 12 महीनों से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उन्हें निष्क्रिय माना जाएगा.

ऐसे वॉलेट पर अब हर तीन महीने में 100 रुपये का इनएक्टिविटी शुल्क लगाया जाएगा. हालांकि यह शुल्क केवल वॉलेट में उपलब्ध बैलेंस से ही काटा जाएगा. कंपनी ने साफ किया है कि इसका असर यूपीआई भुगतान या बैंक खाते पर नहीं पड़ेगा. फोनपे के इस फैसले के बाद कई यूजर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह नियम किस पर लागू होगा और क्या उनके बैंक खाते से भी पैसे कटेंगे. कंपनी ने इन सभी आशंकाओं को दूर करते हुए बताया है कि नया नियम केवल फोनपे वॉलेट के लिए है, न कि यूपीआई सेवा के लिए

फोनपे वॉलेट एक डिजिटल बटुआ है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को पहले अपने बैंक खाते से पैसे जोड़ने होते हैं. इसके बाद उसी बैलेंस का इस्तेमाल भुगतान के लिए किया जाता है. वहीं यूपीआई के जरिए भुगतान सीधे बैंक खाते से किया जाता है और प्रत्येक लेनदेन के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता होती है. कंपनी के अनुसार नया इनएक्टिविटी शुल्क केवल वॉलेट पर लागू होगा, जबकि यूपीआई उपयोगकर्ताओं को किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. फोनपे के मुताबिक यदि किसी वॉलेट में लगातार 12 महीने तक कोई वित्तीय लेनदेन नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा. ऐसे वॉलेट से हर तिमाही 100 रुपये शुल्क काटा जाएगा.

> कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इनएक्टिविटी शुल्क केवल वॉलेट में उपलब्ध बैलेंस से ही वसूला जाएगा. यदि वॉलेट में कोई राशि नहीं है, तो न तो बैंक खाते से पैसे काटे जाएंगे और न ही वॉलेट बैलेंस माइनस में जाएगा. इसलिए जिन उपयोगकर्ताओं के वॉलेट में शून्य बैलेंस है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है

स्पिंज ने मप्र में लॉन्च किया नया 10 डी-टैन फेस पैक

भोपाल, 23 जून. केविनकेयर के लोकप्रिय स्किनकेयर ब्रांड स्पिंज ने मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए अपना नया स्पिंज डी-टैन फेस पैक पेश किया है. यह आसान और प्रभावी फेस पैक केवल 15 मिनट में त्वचा से टैन हटाकर उसे सैलून जैसी चमक देने का दावा करता है. इस लॉन्च के साथ स्पिंज ने अपनी स्किनकेयर श्रृंखला को और मजबूत किया है, जिसे पहले से ही स्पिंज बीबी क्रीम और भारत के पहले बीबी फेस पाउडर जैसी नवाचारपूर्ण पेशकशों के लिए उपभोक्ताओं का भरपूर प्यार मिला है. स्पिंज का नया डी-टैन फेस पैक त्वचा की प्राकृतिक चमक को सिर्फ 15 मिनट में लाने में मदद करता है.

पहले घर का गौरव : कैसे पीएमएवाई बदल रही है पीढ़ियों का भविष्य

अपना पहला घर खरीदना हर परिवार के लिए एक बड़ा सपना होता है. यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, बचत और उम्मीदों का परिणाम होता है। हालाँकि, छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले कई परिवारों के लिए लंबे समय तक यह सपना दूर की बात बना रहा। संपत्ति की बढ़ती कीमतों और सीमित बचत के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना आसान नहीं था। ऐसे में, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ने किफायती आवास को बढ़ावा देकर इस दूरी को कम करने का काम किया है।

ऋषि आनंद, एमडी एवं सीईओ, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अनुसार अपना घर होने से परिवारों को स्थिरता का एहसास मिलता है और भविष्य की योजना बनाने का आत्मविश्वास बढ़ता है। किराए पर खर्च होने वाली राशि धीरे-धीरे एक ऐसे निवेश में बदल जाती है, जो परिवार की अपनी संपत्ति बनती है और लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। एक स्थायी घर बच्चों को स्थिर पारिवारिक माहौल और निरंतर शिक्षा का अवसर देता है, वहीं परिवार को समाज और समुदाय से मजबूत जुड़ाव भी मिलता है। फरवरी 2026 तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 13.61 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे लाखों परिवार अपने घर के सपने के और करीब पहुँच रहे हैं।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत घर खरीदने को अधिक किफायती बनाना है। कई परिवार इस चिंता में रहते हैं कि वे होम लोन की किश्तें नियमित रूप से चुका पाएँगे या नहीं। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत मिलने वाली ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) इस बोझ को कम करने में मदद करती है। इससे होम लोन अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है और परिवारों के लिए घर खरीदने का फैसला लेना भी आसान होता है।

पीएमएवाई महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी अहम् भूमिका निभा रही है। इसके तहत स्वीकृत करीब 74% घर या तो महिलाओं के नाम पर हैं या पति-पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में हैं। महिला के नाम संपत्ति होने से उसकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है, परिवार के फैसलों में उसकी भागीदारी मजबूत होती है और सामाजिक सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिलता है।

इसका असर खास तौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में दिखाई दे रहा है, जहाँ बेहतर बुनियादी ढाँचे, रोजगार के बढ़ते अवसरों और हाउसिंग फाइनेंस तक आसान पहुँच ने अधिक परिवारों को घर खरीदने के लिए प्रेरित किया है। 'अपना घर किसी मंजिल का अंत नहीं, बल्कि कई नए सपनों की शुरुआत होता है।' किफायती आवास को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के लाखों परिवारों को घर का मालिक बनने में मदद कर रही है। इसके साथ ही यह आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और अधिक सुरक्षित भविष्य की नींव भी तैयार कर रही है।

समाचार विशेष

पहले ममता, फिर उद्धव अब अखिलेश की बारी!

सपा में भी भड़की फूट की चिंगारी? राजभर के दावे से मचा हड़कंप

लखनऊ. सुहेलदेवे भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है. दरअसल, उन्होंने अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया है.

पहले प. बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के 20 से अधिक सांसदों को अन्य पार्टी में शामिल होने और फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों को एकनाथ शिंदे गुट में जानें की अटकलों के बीच राजभर ने यह

बयान दिया है. सुभासपा नेता इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. यह कोई पहली घटना नहीं है, जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला हो, इससे पहले भी वह लगातार सपा प्रमुख और पार्टी पर हमलावर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए एक पोस्ट में ओपी राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट होगी. अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि सपा के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक एक चिट्ठी लिखी है.

> **'पूरी सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार'**
>
> एक्स पर किए पोस्ट में ओम प्रकाश राजभर ने लिखा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी. राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है. खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है. शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है. महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है.

शरद पवार की मुश्किलें बढ़ीं

मुंबई. संसद के मानसून सत्र से पहले महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा क्षत्रप शरद पवार की मुश्किलें बढ़ी हैं. उद्धव ठाकरे की शिव सेना में टूट की खबरों के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी शरद पवार की एनसीपी में है.

कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार की पार्टियों के महाविकास अघाड़ी ने पिछले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और राज्य की 48 में से 31 सीटें जीती थीं. लेकिन चार महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियां का बुरा हाल हो गया. अब उद्धव ठाकरे के नौ में से छह या सात सात सांसद एकनाथ शिंदे की शिव सेना में जा रहे हैं. इस बीच शरद पवार की एनसीपी के आठ सांसदों में से पांच या छह के टूटने की चर्चा शुरू हो गई है. जानकार सूत्रों का कहना है कि शरद पवार की पार्टी के नेता उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वे अपनी पार्टी का विलय सुनेत्रा पवार की एनसीपी के साथ कर दें. अगर ऐसा नहीं होता है तो कई सांसद और विधायक पाला बदल सकते हैं. उनकी पार्टी के सांसद मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के संपर्क में बताए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि अगर विलय हो जाता है तो शरद पवार खेमे के भी कुछ लोगों को महाराष्ट्र सरकार में जगह मिल जाएगी.

क्षेत्रीय दलों में मची महा-बगावत

नई दिल्ली. लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर हार का सामना करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने यह बिल वापस नहीं लिया है. जिससे यह साफ हो गया है कि देर-सवेर भाजपा सरकार एक बार फिर इस बिल को सदन में लेकर आएगी. इस बीच देश में बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और पंजाब में क्षेत्रीय दलों के सांसदों के अपने मूल दल से अलग होकर अलग गुट बनाने की मांग करने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थन देने के मामले सामने आए हैं.

उससे यह संकेत मिल रहा है कि देश में अब भाजपा का कांग्रेस मुक्त अभियान बंद हो गया है. उसकी जगह देश में विपक्ष मुक्त भारत का अभियान दिख रहा है. एक राजनीतिक वर्ग का यह भी मानना है कि यह मध्यावधि चुनाव का संकेत भी है. लेकिन भाजपा ने इससे साफ इनकार किया है.

भाजपा का कहना है कि मध्यावधि चुनाव क्यों कराए जाए. इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तरह चरम पर है. महंगाई नियंत्रण में है. देश में विपक्ष कमजोर है. ऐसे में मध्यावधि चुनाव क्यों कराई जाए.

अगर हाल के घटनाक्रम को देखा जाए तो भाजपा ने सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में किया. जहां उसने सत्ता में परिवर्तन करते हुए उस पर कब्जा कर लिया. लेकिन इससे भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर उस समय हुआ, जब टीएमसी की हार के दो सप्ताह के अंदर ही उसके अंदर बड़ी बगावत सामने आई. उसके 28 में से करीब 20 सांसदों ने भाजपा के साथ जाने का ऐलान कर दिया.

हालांकि, भाजपा ने उनको अपने साथ नहीं लिया. इसकी जगह इन सांसदों ने एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया लेकिन साथ ही कहा कि वे भाजपा सरकार को समर्थन देंगे.

9 में से 7 सांसदों के बगावत की सूचना

इसके उपरांत शिवसेना यूबीटी के 9 में से 7 सांसदों के बगावत की सूचना सामने आने लगी. महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आधिकारिक तौर पर विलय की तैयारी कर रहे और व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसदों की सूची में संजय उर्फ बंदू जाधव (सांसद, परभणी), संजय देशमुख, ओमराजे निंबालकर (सांसद, धाराशिव), संजय दीना पाटिल (सांसद, उत्तर पूर्वी मुंबई), भाऊसाहेब वकचौरे और नागेश पाटिल आष्टीकर शामिल हैं.

विशेष | पलानीस्वामी के सामने एआईएडीएमके को बचाने की चुनौती

विजय, उदयनिधि और अन्नामलाई के बीच मिथुन की एंट्री!

चेन्नई. तमिलनाडु में टीवीके की जीत और सीएम की कुर्सी पर थलपति विजय के कब्जे ने राज्य की दोनों द्रविड़ पार्टियों में मुश्किल में डाल दिया है. डीएमके की तुलना में एआईएडीएमके को अधिक मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है. राज्य की राजनीति में आए बड़े ट्विस्ट का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी के हुए के. अन्नामलाई ने अलग रास्ता चुन लिया है.

बीजेपी के साथ लड़े एडापल्ली के पलानीस्वामी के सामने फिलहाल एआईएडीएमके को बचाने की चुनौती है. चर्चा है कि राज्य की राजनीति जेन जेड की चर्चा के बीच जहां विजय, उदयनिधि स्टालिन और के अन्नामलाई हैं. तो इस सब के बीच मिथुन पलानीस्वामी की भी एंट्री हो सकती हैं.

अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी पर अब धीरे-धीरे दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि डीएमके में एम के स्टालिन के बाद कमान अब उदयनिधि के हाथों में हैं तो वहीं टीवीके के सर्वेसर्वा विजय हैं, उधर अन्नामलाई ने युवाओं को जोड़ना शुरू कर दिया है. ऐसे में पलानीस्वामी के ऊपर अब दबाव बढ़ रहा है. वे पार्टी में बगावत से

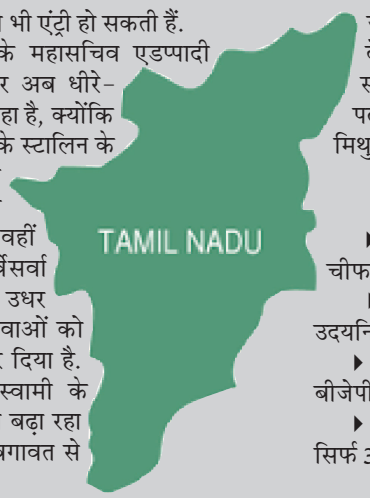

जूझ रहे हैं. पांच विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं. ऐसे में पार्टी के विधायकों की संख्या गिरकर 42 पर आ गई है. एडप्पादी पलानीस्वामी की उम्र 72 साल हो चुकी है. मिथुन अभी 37 साल के हैं.

तमिलनाडु में केंद्र में आई युवा राजनीति

- सी जोसेफ विजय, टीवीके चीफ/मुख्यमंत्री अभी 52 साल के हैं.
- डीएमके चीफ एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि 48 साल के हैं. वे नेता प्रतिपक्ष हैं.
- के. अन्नाईमलाई पूर्व आईपीएस और पूर्व बीजेपी नेता अभी 42 साल के हैं.
- मिथुन कुमार पलानीस्वामी की उम्र अभी सिर्फ 37 साल ही है.

> **अभी तक पर्दे के पीछे रहे हैं मिथुन**
>
> अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी के बेटे मिथुन ने अभी तक पार्टी और चुनाव के समय पर्दे के पीछे रहकर काम किया है. तमिलनाडु में जब अगला चुनाव होगा तब एडप्पादी पलानीस्वामी 77 साल के हो जाएंगे. अभी ही उनके फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है. तब तक मुश्किलें और बढ़ेंगी. अभी तक पार्टी के आईटी विंग में सक्रिय रहे मिथुन के एलीवेशन की मांग उठने लगी है. चर्चा है कि क्या उन्हें आईटी विंग से महासचिव तक की कमान मिलेगी. चर्चा है कि मिथुन को एआईएडीएमके का चेहरा बनाया जा सकता है. पार्टी ने इस तरफ सोचना शुरू कर दिया है. जूनियर विकटन की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव एडप्पादी पलानीस्वामी के सामने बार-बार एक समूह द्वारा रखा गया, जिसमें केरल के पूर्व गवर्नर, एक पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी, एडप्पादी पलानीस्वामी के बहनोई वेंकटेश, सलेम इलांगोवन और एडप्पादी के रिश्तेदार शशिप्रभु शामिल हैं.